भी रामनिषाः, निर्माः यह सही है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में पत्न लिखे हैं। उन पत्नों में जो दलीलें दी गई हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

SHRI PILOO MODY: Government were good enough to increase the age limit to 25 as recently as in May, but there are several departments of the Government which are still not seized of this particular information. For instance, the Income-tax Commissioner of Ahmedabad is supremely innocent that Government have passed such a regulation. May I know whether Government would make sure that all their departments are informed in time?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Yes, we shall do so.

MR. SPEAKER: Next question. Shri Somnath Chatterjee. The hon. Member is absent.

Next question. Shri P. M. Mehta. The hon. Member is absent. Next question. Shri Hari Singh. He is also absent. Then, Shri S. A. Muruganantham. He is also absent. वे जो प्रश्न करने हैं इनको हाजिर रहना भी चाहिए। जो प्रश्न करते हैं, उन पर मवर्नमेंट का खर्ष होता है, सब कुछ होता है।

डा॰ गोबिन्द हास रिखारिया : किसी
मेम्बर का प्रश्न एजंडे पर प्रा गण उस प्रश्न
को करने का प्रगले व्यक्ति को प्रधिकार
मिलना चाहिए । जिस प्रश्न को लाटरी में
स्थान मिल गया प्रगर उसका यहां उत्तर
नहीं दिया जाता है तो इसका प्रथं यह है कि
किसी और का प्रधिकार छिन मया । प्रगर
कोई माननीय सदस्य प्रस्वस्थ हो गया या
किती कारणवंश ग्रा नहीं सका ग्रीर वह प्रश्न
एजंडे में ग्रा गया तो हाउस का यह जो ग्रीधकार
है इस ग्रिधकार को छीना नहीं जाना चाहिए।

स्रम्यका महोदय: मेम्बर नहीं स्राता है तो वह छीन लेता है।

Then, Q. No. 136. Shri D. K. Panda. He is absent. Then, Dr. H.P. Sharma. He is also absent.

डा॰ योकिन्स वास रिक्कारिका: सकर सवाल एजंडे पर घा जाये ग्रीर हाउस चाहे तो ग्राप उस सवाल को लेल।

ग्राध्यक्ष महोरय: यह नहीं हो सकता है। रूल्ज इसके बारे में बड़े क्लीयर हैं।

## Strengthening of Planning Machinery at State Level

137. SHRI SARJOO PANDEY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

- (a) whether the Planning Commission has decided to strengthen the planning machinery at the State level;
- (b) if so, the suggestions made by the Commission in this respect: and
- (c) the assistance being provided to the States for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir.

- (b) A statement is laid on the Table of the House.
- (c) The Centre would reimburse upto two-thirds of the additional expenditure to be incurred by the States on the strengthening of the planning machinery at the State level.

## STATEMENT

The Planning Commission has made the following suggestions for strengthening the planning apparatus at the State level:

(a) There should be an apex body at the State level with the Chief Minister, the Finance Minister, the Planning Minister and technical experts representing various departments and disciplines.

- (b) The work of the apex body should be supported by Steering Groups set up under the Chairmanship of technical experts preferably from outside the Government, in the fields of agriculture, industry, irrigation and power, social services transport, manpower and employment and other important functional fields. The Chairman of these Steering Groups should be members of the apex planning body described at (a) above.
- (c) To ensure that the apex planning body is effective is guiding plan formulation as well as the monitoring of plan implementation, a non-official full-time Deputy Chairman should be appointed to be in charge of the apex body. The Deputy Chairman will function through the State Planning Department which should be the Secretariat of the apex planning bodies.
- (d) In order to enable the Planning Department to discharge adequately its secretarial functions for the apex planning body, its strength should be suitably augmented with experts belonging to various disciplines, the Department should also be functionally reorganised into different units which should mainly be the following:
  - Perspective Planning Unit—dealing with preparation and updating of Resource Inventories and preparation of long-term perspective plans;
  - 2. Monitoring. Plan Information and Evaluation Unit:
  - Project Formulation Unit\_To assist various departments in the preparation of investment projects and also to conduct their ex-ante evaluation;
  - Regional district Planning Unit to provide guidance and technical back-up to the regional and district planning authorities; and
  - Plan Coordination Unit—to assess the existing/anticipated level of

development, determine inter se priorities within an integrated strategy for the next five/one year(s), ascertain the availability of manpower, material and financial resources and synthesise spatial and sectoral plans into a balanced and operational plan.

भी सरजू पांडे : जो स्टेटमेंट दिया है उस में तीन चार सुझाव दिये गये हैं राज्य सरकारों को प्लानिंग मशीनरी को स्ट्रेंगथन करने के लिए । एक सुझाव यह भी है कि एक नान भ्राफिशल चेयरमैन बनाया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि इस नान भ्राफिशल चेयरमैन को क्या गवर्नमेंट एप्वाइंट करेगी या उसका चुनाव होगा ? किस भ्रकार से वह नान भ्राफिशल चेयरमैन नियुक्त होगा ?

SHRI MOHAN DHARIA: It is for the State Government to nominate the deputy chairman. There is no question of electing the deputy chairman.

SHRI K. S. CHAVDA; Will it be a Congressman or a CPI member?

SHRI S. M. BANERJEE: It will be a member of the Swatantra Party.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Or from the Cong. (O).

श्री सरक्ष् पांडे : इस बात को देखते हुए कि राज्यों भीर केन्द्र के बीच इस काम में सहयोग भीर समन्वय हो सके, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि लोक सभा के मेम्बर भीर स्टेट भ्रसैम्बलीज के मैम्बर साथ रह कर काम करें ? ऐसी कोई योजना है कि इन सब का सहयोग भी इस काम के लिए लिया जाये ?

SHRI MOHAN DHARIA: We have been requesting all the State Governments to involve the Members of the Assemblies and also Members of the Parliament while formulating the Plan and also while the plans are implemented.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: They have not done so up till now.

## युःचा राकेट केन्द्र केरल के निकट पाकिस्तान में निर्मित अस्त्रास्त्र तथा गोवा नाक्य की बरायवंगी

+

## \*140. भी हुकम चन्द कछ्त्राय : भी नरेन्द्र सिंह :

क्या गृरु मंत्री यह बताने की कृशा करेंगे कि:

- (क) पाकिस्तानी मायुध कारखाने में निर्मित कतिपय शस्त्रास्त्र ग्रौर गोलाबारूद युम्बा राकेट केन्द्र के निकट पाये गये हैं; भौर
- (ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

पुड़ मंत्रालय और कॉमिक विभाग में राज्य मंत्री (भी राम निवास मिथी) : (क) जी हां, श्रीमान् । बताया जाता है कि मीडियम मशीनगन की 523 गोलियां, जिन पर पाकिस्तानी मायुध कारखाने के चिह्न समेत बिदेशी चिह्न थे, वेनी भील (विशेन्द्रम) के निकट रेस की एक खान में पायी गई थीं जिस समय एक टेकेवार रेत निकास रहा था।

(ख) एक मामला दर्ज किया गया है जीर स्नावस्थक जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री हुकम चन्द कछ। ये : क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ? इस अकार के जो तत्व कहां पर मौजूद हैं, बिन का इस में हाय है और जिन की धोर समा अवस्थाओं में संकेत भी या, क्या सरकार ने जन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही की है ? श्री राम नियास प्रिया : इस मामले के सम्बन्ध में केरल सरकार की पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 22 और 23 अक्तूबर, 1972 के बीच रात को ये गोलियां पाई गई। उस के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस इस के बारे में जांच कर रही है। इमारी केन्द्रीय एजेन्सीच भी इस बारे में जांच कर रही हैं कि ये गोलियां कहां से ग्राई, वहां किस तरह पहुंचीं और इस में किन किस का हाय है।

श्री हुकम बन्द कंछ्यां : क्या सरकार ऐसी पालिसी बनायेगी कि यदि विदेशों में बने हिषयार या किसी प्रकार के शस्त्र भारत के किसी भाग में पाये जायें, तो उसकी सारी छानबीन केन्द्रीय सरकार ग्राने हाथ में ले—वह राज्य सरकार से सहयोग ले, लेकिन जांच करने का पूरा काम उस को न सींप कर स्वयं करे ?

श्री राम निवास मिर्शा: हमारे संविधान के ग्रन्तांत ला एंड ग्रांडर का विषय राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में ग्राता है। इसलिए इस प्रकार के जो भी मामले हों, प्राथमिक कर से उन की जांच करने का दायित्व राज्य सरकारों का ही है। इस सन्बन्ध में राज्य सरकारों को जो कुछ भी मदद या सहस्यता की जरूरत होती है, वह हम हमेगा देते रहते हैं। इस लिए माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव दिया है कि इस प्रकार के सारे मामलों की जांच केवल केन्द्रीय सरकार ही करे, मेरे ख्याल से वह हमारे संविधान के विपरीत है भीर इसलिए भमान्व है।